हरियाणा में कॉलेज : पहले वाले तो सम्भलते नहीं नये खोलने की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा सरकार ने इस सत्र से 31 नये कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ये सभी महिला कॉलेज होंगे। इनमें से तीन अकेले फ़रीदाबाद ज़िले के हिस्से आये हैं। फ़रीदाबाद में नचौली, सैक्टर-2 (बल्लबगढ)व मोहना में नये कॉलेज खोले जायेंगे, जबकि चार सरकारी कॉलेज फरीदाबाद में पहले से ही लड़खड़ा रहे हैं।

इन सरकारी कॉलेजों (तिगांव, खेड़ी गुजरान, सैक्टर 55 के निकट, नेहरू कॉलेज व महिला महाविद्यालय सैक्टर 16 ए) हैं। बताया जाता है कि नये खोले जाने वाले कॉलेज में ना तो किसी प्राध्यापक की नियुक्ति की गई है, ना क्लर्कों की और ना ही प्रिंसिपल की। अभी क्योंकि इन नये कॉलेजों की अपनी कोई बिल्डिंग तो बनी नहीं है इसलिये ये गांव के सरकारी स्कूलों में ही चलेंगे। स्पष्ट है कि इन सरकारी स्कूलों को बच्चों की कमी बता कर या तो बन्द कर दिया गया है या बन्द कर दिया जायेगा। फ़िर उनकी बिल्डिंग को खाली करवा कर इन कॉलेजों के हवाले कर दिया जायेगा। अगर कॉलेज के नाम पर अभी वहां चिड़ियां भी नहीं है तो इनको खोलने की इतनी जल्दी क्या है?

आगे बढने से पहले पाठक जान लें कि पहले से चल रहे कॉलेजों की स्थिति क्या है? खेड़ी गुजरान के कॉलेज की अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं है। 3-4 साल पहले शुरू हुये इस कॉलेज में पढ़ाने वाला स्टाफ़ ना के बराबर हैं। प्रिंसिपल जरूर पक्की है क्योंकि उनके पति देव की नियुक्ति कहीं आसपास है।

दूसरे नम्बर पर तिगांव है। इस कॉलेज में स्टाफ़ की स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि कॉलेज भी 15 साल के करीब पुराना हो चला है। इसके बाद महिला महाविद्यालय सैक्टर 16ए है। इसकी बिल्डिंग ठीक-ठाक है और एक स्थायी प्रिंसिपल भी है जो पढाई में कम और चोरी-चकारी में ज्यादा ध्यान रखती है। यहां लगभग 23 पक्के और 18 कच्चे प्राध्यापक हैं और 7-8 पोस्ट खाली हैं।

ज़िले के सबसे पुराने नेहरू कॉलेज में 60 पक्के तो 80 दिहाड़ी में प्रोफ़ेसर हैं। इन पुराने कॉलेजों के प्रिंसिपलों को ही एक-एक नये कॉलेज का कार्य भार सौंपा गया है। तिगांव वाले को सैक्टर 2 का, महिला कॉलेज वाले को नचौली का और नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल को मोहना का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

स्पष्ट है कि जुगाड़ सा बिठा कर नये कॉलेज शुरू करे जा रहे हैं। पहले से चल रहे कॉलेज स्टाफ़ की कमी से पहले ही त्रस्त हैं ऊपर से नये कॉलेजों का अतिरिक्त काम अलग से। यानी नये कालेजों में तो पढाई क्या होगी, पुरानों को भी बर्बाद करने का पूरा इन्तजाम कर दिया है खट्टर महोदय ने। ठीक भी है, ना हम पढें हैं और ना तुम्हें पढ़ने देंगे। बस डुगडुगी पीटेंगे और अपना प्रचार करेंगे कि देखो हमने कद्दू में तीर मार दिया है।

लेकिन सवाल है कि इस सब के लिये इतनी हाबल-ताबल मचाने की जरूरत क्या थी? बिल्डिंग बनाकर, नया स्टाफ़ भर्ती करके भी तो ये कॉलेज शुरू किये जा सकते थे। असल में पढाई तो इन कॉलेजों का उद्देश्य है ही नहीं। इनको खोलने का एक उद्देश्य तो है अगले चुनाव में वाहवाही लूटना और दूसरा है नयी बनने वाले कॉलेजों बिल्डिंगों में करोड़ों रुपये कमीशन डकारना। बच्चे पढें या भाड़ में जायें, प्राध्यापक पढायें न पढायें या इस कॉलेज से उस कॉलेज में धक्के खाते फिरें, इनकी बला से, इनको तो मतलब है कि इन 30-32 कॉलेजों की बिल्डंगों के अगले चुनावों से पहले ठेके दे कर करोड़ों रुपये पर हाथ साफ़ करना। बाकी आने वाली सरकार रोयेगी ही कि हाय सारा खजाना खाली कर गये।

मेवला महाराजपुर में न बिजली बिल जमा हुए, न चोरी रुकी, कर्मचारियों की पिटाई अलग से

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के गांव में बढती गुंडागर्दी नये कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। यहां के लोग़ों पर बिजली के 11 करोड़ के बिल बकाया हैं। गुंडागर्दी के आगे लम्बी लेटी हुई सरकार ने बिलों पर लगे जुर्माने को माफ़ करने की पेशकश करते हुए 11 करोड़ के बिलों को 8 करोड़ कर दिया था। मार्च 2018 में दी गयी इस रियायत के बावजूद बिजली विभाग के पल्ले कुछ नहीं पड़ा।

अकेले इस गांव में दी जाने वाली बिजली का 50 प्रतिशत भाग सीधे-सीधे चोरी हो जाता है। यानी मंत्री गूजर के संरक्षण में यहां के दबंगों को मीटर लगवा कर बिजली लेने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। वे सीधे तारों में कुंडी डालकर खुले आम बिजली चोरी करते हैं। चोरी की जा रही इस बिजली का कोई हिसाब बिजली विभाग के पास नहीं है, अर्थात् बकाया बिलों की 11 करोड़ राशि में चोरी की जा रही बिजली का कोई खाता नहीं।

बिजली की इस चोरी को रोकने के लिये चोरों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करने के बजाय सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके बिजली की नंगी तारों की जगह कवर्ड केबल व नये मीटर लगाने शुरू किये। जब कर्मचारी यह काम कर रहे थे तो दबंगों ने दो बिजली कर्मचारियों को इस लिये पीटा कि उन्होंने दबंगों के लिये कुंडी कनेक्शन देने से मना कर दिया था। इसके अलावा जगह-जगह से केबल को काट कर फ़िर से कुंडी कनेक्शन लगा लिये गये हैं।

इस मामले में कार्यवाही के नाम पर थाना सूरजकुंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की खानापूर्ति तो कर दी है लेकिन इससे आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। नज़र आये भी कैसे जब कृष्णपाल भये मंत्री तो डर काहे का।

हरियाणा बिजली बोर्ड के सीएमडी शत्रुजीत कपूर, जो फ़रीदाबाद में पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, एक हाई-फ़ाई शादी में शामिल होने 11 मई को आये तो जरूर लेकिन मंत्री के संरक्षण में चलने वाली इस खुली बिजली लूट के प्रति आंख मीचे रहे। आंख खुले तो इस मलाईदार पोस्टिंग पर बादल मंडरा सकते हैं।

कठुआ का हिंदू-मुस्लिम सच; कीमत देश को अदा करनी होगी!

कठुआ से विवेक की विशेष रपट

कठुआ पहुंचने से पहले ही कठुआ का हिन्दू-मुस्लिम सच ट्रेन की मेरी बोगी में सामने आने लगा।

मेरे कम्पार्टमेन्ट में ही बैठे फ़ौजी ने अखबार पढ़ते हुए कहा कि साले कश्मीरियों को मारो चुन-चुन के जो पत्थर मारते हैं, तभी कश्मीरी लड़कियां जो इसी कम्पार्टमेंट में बैठी थीं बोल पड़ीं कि आपको कश्मीर बुलाया किसने है जो आप आ बैठे हैं हमारे कश्मीर में। आपके पास गोली है तो गोली मारो, हमारे पास पत्थर हैं तो हम पत्थर मारेंगे।

एक बी.एस.एफ़ अधिकारी जो साथ में ही यात्रा कर रहे थे बोले, हम जान पर खेल कर देश सेवा करते हैं तो इस पर एक बुजुर्ग जो कश्मीरी पंडित थे एवं विस्थापन के उपरांत जम्मू में बसे, ने जवाब दिया कि भाई साहब आप रोज़गार के लिये भर्ती हुए हैं। अगर देश सेवा का इतना ही जुनून है तो ज़रा मुफ़्त में दो महीना काम कर के दिखाओ। दोष ना फ़ौज का है ना कश्मीरी नागरिकों का। दोष सरकार का है जिसने जनता और सेना को आमने-सामने खड़ा कर दिया है।

पिछले दिनों कठुआ की आठ वर्षीय बालिका का बलात्कार एवं कत्ल अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा। इसी क्रम में अफ़वाहों का बाज़ार भी गर्म होता गया है।

ज़मीनी हकीकत जानने के लिये कठुआ जाकर वहां के स्थानीय लोगों से बात करने से एक ऐसा पक्ष सामने आया जिसमें भारत की अखंडता खंडित होती लग रही है।

29 वर्षीय विकल्प वैद्य जो कठुआ में बतौर बैंकर कार्यरत हैं, का मानना है कि बतौर बैंकर कठुआ में कार्यरत हैं का कहना है कि यह मामला राजनीतिक खिचड़ी मात्र है। चार महीनों से वो लोग कहां थे जो आज पीड़िता के लिये न्याय मांग रहे हैं? जो लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, सब कांग्रेस के इशारे पर आए हैं।

विकल्प के अनुसार राज्य की मुफ़्ती सरकार कश्मीरी मुसलमानों को खुश करना चाहती है। इसलिये केस की जांच पहले मुस्लिम अफ़सरों को दी गई। ये अफ़सर जान-बूझ कर कत्ल का इल्ज़ाम हिंदुओं पर डाल रहे हैं और साथ ही बलात्कार जैसा झूठा आरोप लगाकर केस को मजबूत करना चाहते हैं। परंतु वहीं जब विकल्प से भाजपा के विधायकों और मंत्रियों का आरोपियों के पक्ष की रैली में शामिल होने पर पूछा गया तो उन्होंने उसे हक़ की लड़ाई बता दिया।

रिटायर्ड बैंकर आर के जामवाल के अनुसार, गुर्जर जनजाति के दूधिया एवं बक्करवाल दो समुदाय हैं। जम्मू कश्मीर के लिये ये समुदाय बहुत घातक हैं। यह लोग भारत की खुफ़िया जानकारी सीमा पार पाकिस्तान को देते हैं। इस लिये इनको किसी भी तरह से जम्मू-कश्मीर से निकाल फ़ेंकना होगा।

शिवम जिसने अभी बारहवीं की परीक्षा दी है और सेना में जाने की इच्छा रखता है, ने सारे प्रकरण को मुस्लिमों की चाल कहा। शिवम का मानना है कि हिंदू बिखरे हुए हैं, एवं मुस्लिम संगठित हो कर कठुआ जैसी घटनाओं को खुद अंजाम देकर हिंदुओं के खिलाफ़ चाल चल रहे हैं।

शिवम ने बताया कि आरोपियों में से एक लड़के की वीडियो क्लिप उसी समय एटीएम में मिली है जिस समय बलात्कार हुआ बताया गया। परन्तु शिवम से जब यह पूछा गया कि लड़की तो कई रोज़ तक बंधक थी तो आरोपी के किसी समय एटीएम में होने से क्या साबित होता है? इस पर शिवम लाजवाब दिखा। परंतु वह यह मानने को तैयार नहीं कि कोई बलात्कार हुआ होगा। या किसी हिंदू ने पीड़िता की हत्या की होगी।

लगभग सभी लोग़ों ने बात-चीत के दौरान एक बात कही कि जम्मू-कश्मीर के नए कानून के मुताबिक यदि कोई बक्करवाल किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले तो वह ज़मीन उसकी हो जायेगी। ज्यादातर लोगों का मत था कि अपनी भूमि से कब्ज़ा हटाने के लिये आरोपी साजीराम ने सिर्फ़ डराने के लिये अपहरण किया था लड़की का। बलात्कार की बात सरासर झूठी है एवं कत्ल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये।

क्राइम ब्रांच की जांच के उलट, स्थानीय निवासी किस आधार पर यह फैसले दिए जा रहे थे? उसकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। ज्यादातर को ये जानकारियां वाट्सएप से प्राप्त हुई हैं।

बक्करवाल समुदाय के ही शेखू एवं अतर नामक दो नौजवान बक्करवाल मुझे कठुआ शहर से 9-10 किलोमीटर दूर बकरियां चराते मिले। शुरुआती झिझक के बाद वे बात करने को तैयार हुये। शेखू ने केस की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ-साथ अपने समुदाय की सुरक्षा की मांग भी की।

अतर ने कहा कि भारतीय नागरिक होने के नाते उनको भी अधिकार है कि कानून के सामने उनसे समानता का व्यवहार हो और साथ ही इस केस को एक निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिलना चाहिये।

पास ही बकरियां चराते 70 वर्षीय बक्कर वाल लाला गुर्जर जो दूधिया के कारोबार से अपना घर चलाते हैं, ने भावुक स्वर में बताया कि आज वह डर के साये में जी रहे हैं। 1971 एवं 1998 में भारतीय फ़ौज की भरपूर सहायता करने के बावजूद उन्हें पाकिस्तानी बुलाया जाना अत्यंत पीड़ादायक है। ऊपर से यदि उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं होंगे तो वे लोग कहां जायेंगे कठुआ में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि बलात्कार/हत्या को लेकर हिंदू मुस्लिम दो धड़ों में बंट गए हैं। न्यायपालिका जो भी फैसला दे, जनता वही मान चुकी है जो भी मानना उसे सुलभ प्रतित हो रहा है। वॉट्सएप की अफ़वाहें रोज़ नया कुतर्क परोस कर समाज को किस कदर बांट चुकी हैं इसका खामियाजा भरतीय समाज को चुकाना तय प्रतीत होता है।

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से शुरू होगा मोदी मुक्त भारत का श्रीगणेश

पर सवाल ये कि क्या सिद्धारमैया से नाराजगी के बीच कांग्रेस ऐसा कर पाएगी

बेंगलुरु से मनोरमा की रिपोर्ट

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 एक ओर कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने के साथ साथ नाक का सवाल है तो वहीं भाजपा में सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसलिए मोदी—शाह की जोड़ी महीने भर से भी पहले से पूरे राज्य में मैराथन रैली, रोड शो, सभाएं करने में व्यस्त हैं।

मोदी—शाह के सीधे निशाने पर राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के लिए फिलहाल अपनी पूरी उर्जा कर्नाटक में ही लगा रखी है।

इन सबके बीच राज्य के चुनाव परिणामों को लेकर विशेषज्ञों का आकलन, भविष्यवाणियां और विश्लेषण भी जारी है। सबसे पहले भाजपा की सरकार बनने का सर्वे आया फिर कांग्रेस को बहुमत मिलने की बातें हुई और अब त्रिशंकु विधानसभा की बात हो रही है। बहरहाल, परिणाम 15 मई को नतीजे आ जाने के बाद तस्वीर साफ हो ही जाएगी, लेकिन इन सबके मद्देनजर ये भी सच है कि चुनाव में हार जीत का दारोमदार स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा रहता है।

केन्द्र की भाजपा सरकार ने पिछले चार सालों में क्या किया इससे ज्यादा लोगों के लिए ये मायने रखता है कि पिछले पांच साल में सिद्धारमैया ने कर्नाटक में क्या किया। हालांकि अगर कर्नाटक में भाजपा हारती है तो यह मोदीमुक्त भारत का श्रीगणेश भी होगा।

10 में से 7 ओपिनियन पोल कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट दिला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 35 सालों में कांग्रेस को कभी भाजपा से कम वोट नहीं मिले। हालांकि तमाम नाराजगियों के बीच आम लोगों की भी यही राय है कि जो भी है कांग्रेस मोदी की भाजपा से तो बेहतर ही है। 1983 से लेकर 2013 तक के सभी चुनावों में सिर्फ 1999 में ऐसा हुआ कि कांग्रेस को 34 प्रतिशत से कम वोट 28.95 प्रतिशत पड़े।

अगर बात करें सिद्धारमैया सरकार की तो तमाम तारीफों और आलोचनाओं के बीच ये भी सच है कि बेंगलुरु शहर की 27 सीटों पर (भाजपा विधायक और उम्मीदवार की मौत के चलते एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है) वोट स्थानीय मसलों के आधार पर भी डाले जाएंगे।

लेकिन इस संदर्भ में सरकार का रिपोर्टकार्ड उतना प्रभावशाली नहीं है, खासतौर पर सड़कों, बुनियादी सुविधाओं, ट्रैफिक, पीने का पानी, झीलों की साफ सफाई और उनके प्रदूषण पर रोक तथा कचरा प्रबंधन इन सभी मोर्चों पर सरकार का काम ढीला रहा है।

बुनियादी ढांचे की उपेक्षा से विशेष रूप से आईटी सेक्टर के लोगों में कुछ नाराजगी है। बात अगर कचरा प्रबंधन की करें तो बेंगलुरु शहर की ये सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है यहां तक कि पिछली बरसात में कोरमंगला में आये बाढ़ का कारण नालियों का कचरे से बंद हो जाना था, वो भी तमाम मॉल्स व फ्लिपकार्ट, आमेजन जैसी ऑनलाईन शॉपिंग कंपनियों के पैकिंग कचरे के नालियों में डंप किए जाने के कारण। सरकार की ओर से इन हालात के लिए कोई प्रभावी रूपरेखा नहीं है, न ही मॉल्स और कंपनियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई।

शहर की गरीब बस्तियों और झुग्गी या स्लम इलाकों के हालात बदतर हैं, जहां ना पीने का साफ पानी है, ना ही शौचालय और ना कचरा प्रबंधन, जबकि कांग्रेस का इन्हीं इलाकों में सबसे मजबूत जनाधार है। कर्नाटक स्लम विकास आयोग के मुताबिक राज्य में 2804 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें से अकेले बेंगलुरु में ही 597 स्लम हैं। शहर का हर पांचवा व्यक्ति स्लम में रहता है और राज्य की कुल तीस से चालीस फीसदी आबादी स्लम और गरीब बस्तियों में रहने को अभिशप्त है।

कर्नाटक विधानसभा में बेंगलुरु की सीटों का योगदान 10 फीसदी का होता है। पिछले चुनाव में यहां की कुल 28 सीटों में से कांग्रेस को 13, भाजपा को 12 और जेडीएस को 3 सीटें मिली थीं। यानी चुनाव जीतने के लिए बेंगलुरु की अनदेखी नहीं की जा सकती, खासकर तब जबकि भाजपा मुख्य रूप से शहरी लोगों की पार्टी है।

इसीलिए पिछले छ: महीने से सिद्धारमैया ने बेंगलुरु की सुध लेना शुरू किया है, चाहे सड़कों का निर्माण या मरम्मत हों या झीलों की साफ सफाई का काम, बेंगलुरु के लिए दस हजार करोड़ के पैकेज की भी घोषणा हुई है, लेकिन ये काफी नहीं है। लोगों में गुस्सा है, कचरा प्रबंधन के मसले पर शहर के तमाम बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग भी एकजुट हैं और दलगत राजनीति से अलग हटकर लोगों से काम करने वाले उम्मीदवारों का चयन करने की अपील कर रहे हैं।

नागरिकों में वोट डालने के अभियान का प्रचार कर रहे समकारा बैंड के तीर्थो मुखर्जी कहते हैं हमारी टीम के लोग शहर के तमाम इलाकों में लोगों को 12 मई को वोट डालने के लिए निकलने को कह रहे हैं और किसी भी दल के सबसे बढ़िया उम्मीदवार को चुनने की अपील कर रहे हैं।

इसी तरह बेंगलुरु पोलिटिकल एक्शन कमिटी या बीपैक जैसी नागरिक संस्थाओं ने योग्यता के आधार पर अच्छे उम्मीदवारों की सूची बनाई और उनके लिए अपनी ओर से प्रचार कर रही हैं। मसलन, इस चुनाव में बीपैक ने भाजपा के 8, कांग्रेस के 12,आप के तीन, स्वराज इंडिया के एक और 22 निर्दलीय उम्मीदवारों का चयन किया है और इनके लिए प्रचार कर रहे हैं साथ ही जरूरी होने पर चुनाव लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में अखबारों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सर्वेक्षण में कांग्रेस की जीती पिछली 13 सीटों की मुख्य समस्या कचरा प्रबंधन ही थी, इसके अलावा पेयजल और शौचालय की, चाहे बेंगलुरु का सबसे बड़ा स्लम राजेन्द्र नगर हो या गांधी नगर, कोरमंगला,व्हाईटफील्ड, बेलान्दूर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे इलाकों के स्लम सभी बेहाल हैं।

महादेवपूरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कादूबीसन्नाहल्ली के राजा रेड्डी लेआउट के इनसाईट ऐकेडमी से लगे इस इलाके की सड़कों से ही नर्क की परिकल्पना साकार होने लगती है। सड़क से गली तक कचरे का अंबार, रुका हुआ सड़ चुका पानी, आवारा कुत्ते, सुअर और चारों ओर से आती तेज दुर्गंध, लेकिन यहीं लगभग 500 लोग भी रहते हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंढ और असम से आकर गार्ड, कुक और ड्राईवर की नौकरी और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। यहीं रह रहे सुमित पटेल बताते हैं सात हजार किराए पर एक कमरा लेने पर भी ना किचन है ना शौचालय। चार लोग मिलकार कमरा शेयर करते हैं। अकेले उनके गाजीपूर ढाई सौ के करीब लोग हैं, सात—आठ साल बेंगलुरु में रहने के बाद भी ना वोटर आईकार्ड बना है इन लोगों का और ना ही कोई सहूलियत ही मिली है। सुमित बताते हैं यहां 10—12 औरतें भी रहती हैं, लेकिन कमरों में शौचायल बगैर छत और दरवाजे के हैं, जिनमें ना नल है न ही पानी। ये ऐसे इलाके हैं जहां न कोई नेता जाता है और न ही प्रशासन के लोग। शहर की ऐसी तस्वीर सिर्फ इसी इलाके की नहीं है, बल्कि कई जगह ऐसे या इससे भी खराब हालात हैं। जाहिर है जनता चुनाव में सवाल पूछेगी ही और वोट के रूप में जवाब भी देगी ही।